



PG-5

# आधुनিক सমাচার

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक



PG-5

वर্ষ -08 अंक -168

प्रयागराज, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022

पृष्ठ- 8

मूल्य : 2.00 रुपये

## संक्षिप्त समाचार

अनाथ' शब्द से नहीं

जुड़ा कोई कलंक,  
इसे बदलने की नहीं

जरूरत मुंबई हाईकोर्ट

(आधुনিক समাচार सेवा)

मुंबई उच्च न्यायालय ने

गुरुवार का एक जनहित याचिका

(पीडीएफ) को खालिज कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि 'अनाथ'

शब्द से कोई सामाजिक कलंक

नहीं जुड़ा हुआ है।

इस शब्द का

अर्थ है अनाथ और असाध्यका नहीं

है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर

दत्ता और न्यायमुर्ति माधव

जामिदार की खेड़ीठोंठ एन्जीओ

स्वानाम फाउंडेशन द्वारा दायर

जनहित याचिका पर सुनवाई कर

रही थी, जिसमें 'अनाथ' शब्द को

'स्वनाम' भौलने की मांग की

गई थी। याचिका में दाव किया

गया है कि जिन बच्चों ने अपने

माता-पिता को खो दिया है वे पहले

से ही एक कमज़ोर स्थिति का

सामना कर रहे हैं और 'अनाथ'

शब्द एक जरूरतमंद,

असाध्य

और वैशिष्ट्य बढ़े के रूप में उन्हें

दर्शाता है और 'स्वनाम' शब्द का

अर्थ होगा आत्मनिर्भर और

आत्मविश्वासी बच्चा। हालांकि

पीड़ितों ने कहा कि यह ऐसा मामला

नहीं है जिसमें अदालत को

हस्तक्षेप करना चाहिए। सीज़े

दत्ता ने कहा, कभी-कभी हमें भी

लक्षण रेखा खींची पड़ती है

और हम मामले में हस्तक्षेप नहीं

करना पड़ता है। अदालत ने

याचिका को खालिज कर दिया

और अनाथ शब्द संदर्भों

से प्रयोग में है। हम याचिकाकर्ता

से सहमत नहीं है कि 'अनाथ'

शब्द जो उन बच्चों को संदर्भित

करता है जिन्होंने अपने माता-पिता

को खो दिया है, किसी भी

सामाजिक कलंक से जुड़ा हुआ

है। इस शब्द में बदलाव की

विलुप्त भी असाध्यकता नहीं है।

पीड़ितों ने कहा कि याचिकाकर्ता

चाहता है कि इस शब्द को

बदलकर 'स्वनाम'

कर दिया जाए जो कानूनी

को एन्जीओ का नाम है। कोर्ट

ने पूछा, 'अनाथ' शब्द में ऐसा क्या

है जो सामाजिक कलंक है।

मैके का फायदा अपने हितों को

साधने के लिए उठाना चाहता है।

इससे भारत एक ही तीर से दो

निशाने भी साथ सकता है। भारत

गैस की खरीद कर अपनी ऊँझी

की बाधित किया गया

है। ऐसे में एक तरफ

जहां पूरोगे के देश

एन्जीओ क्राइसेस के

बाद दूसरे विकल्पों

को लाला करने में

जुट गए हैं वहीं

दूसरी तरफ दूसरे गैस

कीमत पर भारत को

मुश्यों का घर बनाने में जुटा है।

भारत भी इस

## कोविड के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को टैक से उतारा

(आधुनिक समाचार सेवा)

नई दिल्ली। कोविड वैश्विक महामारी

ही है दुनिया के कई हिस्सों में

जारी संघर्षों से मध्ये भारी उत्तर-युद्ध

का आकलन किया गया है।

इसमें से दोनों

ने लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा

प्राप्त करने के लिए नए दृष्टिकोण

लाए जाने की पैरोकारों को

प्रगति के सभी सकें अब तक के

अपने-अपने लेंडों में फॉउंडेशन की

सह अध्यक्ष मैलिंडा फ्रेंच गेट्स

विल गेट्स ने वैश्विक संकर के प्रभावों

का आकलन किया है।

इसमें से दोनों

ने लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा

प्राप्त करने के लिए नए दृष्टिकोण

लाए जाने की पैरोकारों को

गहनी होती है। वहीं मिलिंडा फ्रेंच गेट्स

कहती है कि दुनिया कई चुनौतियों

का सामना कर रही है - जिनमें से

कुछ दुर्मिल लगा सकते हैं।

पर भी, असफलताओं के बावजूद हम इन

समस्याओं को हल कर सकते हैं।

नवाचार के माध्यम से लाखों लोगों

की जान बचा सकते हैं। रिपोर्ट में

रोकथाम योग्य संकामक रोगों और

वृषोधारण को समाप्त करने,

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में

सुधार, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच

के खाली खाली खाली खाली खाली

के खाल









# सम्पादकीय

जोड़ने वाले ही विपक्ष को  
तोड़ने में जुटे, आखिर कैसे  
बैठेगा इन दलों का गणित

जिन पर घर बनाने का जिम्मा हो, वही घर गिराने लगे तो उन लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जो घर बनाने का इंतजार कर रहे हैं। अपने देश में विपक्षी एकता का यही हाल है। ज्यादातर त्योहार साल में एक बार आते हैं, पर विपक्षी एकता का त्योहार हर पांच साल में एक बार आता है। आम चुनाव से पहले इसकी शुरूआत होती है और उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात। इस समय विपक्षी एकता का मौसम चल रहा है, पर बयार उलटी बह रही है। दल ज़ुड़ने से ज्यादा बिखर रहे हैं विपक्षी एकता दो तरह की होती है। एक चुनाव से पहले की ओर दूसरी चुनाव के बाद की। चुनाव से पहले की एकता चुनावी मोर्चे पर सफल हो तो उसे जनादेश कहते हैं। चुनाव के बाद की एकता सत्ता के बटवारे की होती है, पर सत्ता के लिए जनादेश को धता बताने में राजनीतिक दल संकोच नहीं करते। नीतीश कुमार इसके दैयित्यन है। वह गठबंधन बदलते रहते हैं, पर उनकी कुर्सी नहीं बदलती। नीतीश कुमार इस समय विपक्षी एकता कराने निकले हैं। उनके पास अपना कोई सौदा नहीं है। वह दूसरे का सामान लेकर व्यापारी बने हुए है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का सौदा कराने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। उन्होंने दिली आकर कई नेताओं से मुलाकात की, पर लालू यादव के आशीर्वाद और सोनिया जी के सम्मान का पूरा ध्यान रखा। यह बात किसी से भिन्न नहीं है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में पट नहीं रही। किसी को संदेह रहा हो तो उसे ममता बनर्जी ने एक बार फिर दूर कर दिया। नीतीश कुमार के दिली से जाते ही उन्होंने कहा कि राजद, दण्ड्य, तृणमूल कांग्रेस, सपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ चुनाव लड़ेंगे। वह बयान विपक्षी एकता कराने वाले सभी लोगों के लिए यह संदेश था कि कांग्रेस मंजूर नहीं। दो दिन बाद ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी के भारत लौटे ही उनसे मिलने जाएंगे। मतलब दोनों ने ममता बनर्जी को छिड़क दिया हमंत सोरेन क्या बोल सकते हैं? वह तो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। अधिकेश यादव तो सतत गठबंधन के साथी की तलाश में रहते ही हैं। उथर कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा निकाल रही है। जो 18 दिन केरल में रहेगी, जहां वाम मोर्चे का राज है। वाम मोर्चे ने कहा है कि कांग्रेस में आरएसएस की चुनौती का जवाब देने का साहस नहीं है। इसलिए यात्रा गुजरात नहीं जा रही और उत्तर प्रदेश में चंद दिन ही रहेगी। इसका जवाब यात्रा के कर्णधार जयराम रमेश ने यह कहकर दिया कि केरल में माकपा भाजपा की ए टीम है। याद रहे ये दोनों दल सवा साल पहले बंगल में एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं और विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल रहे हैं। विपक्षी एकता के अश्वमेध घोड़े को लेकर निकले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव लगाता है निराश हो गए हैं। उन्होंने अब अपना राष्ट्रीय दल बनाने की घोषणा कर दी है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी अपने अधिकेशन में विपक्षी एकता का ब्लू प्रिंट पेश करेगी, पर उसकी कोई सुगुणाहट सुनाई नहीं दी। समस्या यह है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हराना तो सब चाहते हैं, पर एक-दूसरे की नीयत को शंका की दृष्टि से देखत है। यदि विपक्षी 27 साल में 23 साल भाजपा के साथ रहने वाले नीतीश कुमार भी भाजपा विरोधी होने का दावा करें तो कोई कैसे भरोसा करेगा विपक्षी एकता में एक समस्या यह भी है कि जो जोर-जोर से कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हैं, वही सबसे तेज दौड़ रहा है। जैसे पगत में खाना खाने वाले कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हमेशा बगल वाले को देने के लिए आवाज लगाते हैं। उनकी नीयत का पता तब चलता है, जब परोसने वाला आ जाता है। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के अंह का भार उनके शरीर के वजन से भी ज्यादा है। कोई अपने को किसी से कम मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी एकता का इतिहास देखें तो चुनाव से पहले या तो एकता होती नहीं, होती है तो सफल नहीं होती और सफल हो भी गई तो चलती नहीं। आजादी के बाद पहला बड़ा विपक्षी गठबंधन बना 1971 में। वह चुनाव के मैदान में धराशायी हो गया। उसके बाद साल 1977 में जनता पार्टी के रूप में विपक्षी एकता हुई, जो चुनाव में कामयाब रही, पर चली नहीं। वही हश्श 1989 में बने जनता दल का हुआ। चुनाव बाद बने गठबंधन भी तभी चले, जब उनकी धूरी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनी। बहुत से लोगों को चिंता है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा का वर्चस्व स्थापित हो रहा है और उसका कोई विकल्प नहीं है।



एकता-अखंडता के स्मरण का उत्सव, हैदराबाद की मुक्ति अनसुनी संघर्ष गाथा सुनाना भी जरूरी

भारत ने पिछले महीने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को यह स्मरणोत्सव हैदराबाद मुक्ति के लिए एसंघर्षरत नेताओं और बलिदान हुए वीरों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोंडा लक्ष्मण बापुजी, शोएब उल्हास खान,

अमर नहीं रखा गया तो इनके योगदान पूरी तरह से भुला दिए जाएंगे। इस दृष्टि से इस स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त, 1947 को

जन विद्रोह को कुचलने के लिए हरसंभव प्रयास किया। लोगों को लूटा, डराया, मारा और महिलाओं का यौन शोषण किया। स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध निजाम

वर्तमान कर्णीटक के उत्तर-पूर्वी जिले बीदर, कालाबुरामी, कोप्पल, विजयनगर, यादगीर और रायचूर भी शामिल थे। इसलिए हैदराबाद की मुक्ति आधुनिक भारत के एकता-अखंडता और स्वतंत्रता का उत्सव है। यह निजाम के आततायी शासन से मुक्ति का उत्सव है। यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का उत्सव है, लेकिन इस



नरेन्द्र मोदी की 'हैदराबाद मुक्ति स्मरणोत्सव' जैसी पहल गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में एक सार्थक कदम है। केंद्र सरकार ने इस स्मरणोत्सव को वर्ष भर मनाने का नियम किया है। इस अवसर पर 17 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ करेंगे।

नारायण राव पवार, स्वामी रामानंद तीर्थ, कोमाराम भीम, सुरवरम प्रतापेड्डी, वंदेमातरम रामचंद्र राव, रामजी गोड, भाग्य रेही वर्मा और चकली इलम्मा जैसे अनेक वीरों के बलिदान हमारी सामूहिक स्मृति से धूधले होते दिखाई दे रहे हैं। यदि इन महापुरुषों के महान कार्यों और अभूतपूर्व तथ्यों को पुस्तकों, स्मारकों और हमारी सामूहिक स्मृतियों में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब 562 रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने की घोषणा हुई। उस समय गुजरात के जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद में इसका विरोध हुआ। हैदराबाद में सातवें निजाम भीर उस्मान अली खान के कूर शासन से जनता व्रस्त थी। निजाम की रजाकार सेना उसके निर्देशों पर दिनोंदिन उग्र हो रही थी और उसने हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ से बाहर रखना चाहता था। वह हैदराबाद रियासत को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था या पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। निजाम के अनुसार हैदराबाद रियासत में वर्तमान तेलंगाना, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद एवं परभणी और

स्मरणोत्सव को निजाम का अपमान करने और मुस्लिम समुदाय को नाराज करने के साथ जोड़ रहे हैं। तुष्टीकरण की यह राजनीति इतनी मजबूत है कि लोग भूल जाते हैं कि एक पत्रकार शोयाबुलाह खान ने निजाम की सेना के अत्याचारों पर लिखा तो निजाम ने उनके दोनों हाथ कट दिए। इसलिए यह हिंदू-मुस्लिम को तोड़ने का नहीं, बल्कि देश की ऋणी है। उस समय यदि वह भारतीय सेना को 'आपरेशन पोल' का आदेश नहीं देते तो शायद आज हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा होता या फिर अलग देश होता। इसलिए इस ऐतिहासिक संघर्ष की गाथा को देश की जनता को बताना जरूरी है, ताकि ये आदर्श आज के युवाओं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा पुंज के रूप में काम करें।

तर सप्ताह बड़े जोर-शोर से कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू हुई। इससे पार्टी समर्थकों, कायदकर्ताओं और इंटरनेट मीडिया योद्धाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। इस दौरान राहल गांधी ने भी नई ऊर्जा और साकृत्या दिखाई है। अमृतन किसी भी राजनीतिक गतिविधि का आकलन भीड़ और संसाधनों के जुटान से लगाया जाता है। इन दोनों पैमानों पर यात्रा ने कांग्रेस के लिए अभी तक अच्छे संकेत दिए हैं। संभव है कि इसकी एक वजह यही हो यह यात्रा का आरंभिक दौर है। दूसरा तमिलनाडु से शुरू होकर इस समय वह केरल में है, जहां कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। बहरहाल, कांग्रेस के हालिया लचर प्रदर्शन को देखते हुए यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया पार्टी को प्रोत्साहित करने वाली है। इसके बावजूद एक सवाल कायम है कि क्या अगले आम चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी मुहिम ही पर्याप्त होगी। कई पहलुओं को देखते हुए इसका अनुमान लगाना कठिन है यह यात्रा एक तरह से राहल गांधी को नए

लिए राहुल ने अभी तक हामी  
भरी हैं। यह मानते हुए कि  
इस रुख पर अभी भी कायम  
नहीं तो राहुल के लिए छवि निर्माण  
इतनी बड़ी कावायद के बाद नए  
व्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी को  
वीरी रूप से संभालना मुश्किल  
नहीं। इस प्रकार के जन जुड़ाव  
अभियानों के वास्तविक लाभ  
नीय और राज्य संगठनों से  
इसके बड़े क्षेत्रों से वहां स्थान  
जायेंगे। कि पाठ नए अधिकारी  
उल्जागार के व्यापारों परिचय  
पाठिय्या है, मगर

मी कोई संकेत नहीं कि जिन याह यात्रा गुजर रही है, वानीय सांगठनिक मुद्दे सुलझ खासतौर से यह देखते हुए वर्षों का केंद्रीय नेतृत्व स्वयं व्यक्त के लंबित चुनाव में से जूँझ रहा है। इस प्रकार एक जनसंपर्क अभियान का चुनावी लाभ उठा सकती भारत जोड़ो यात्रा का मंतव्य

A black and white photograph of a man in a white shirt and white pants, wearing a garland of orange, green, and white flowers, walking outdoors. He is smiling and looking towards the camera. In the background, there are palm trees and other people, suggesting an outdoor event or rally.



**चीन से अभी भी सावधान रहना होगा, उसकी परानी करततों को न भले भारत**

28 महीने के लंबे तनाव और सैनिक अधिकारियों की बातचीत के 16 दौर के बाद भारत और चीन के बीच इस पर सहमति बनी कि पूर्वी लद्धाख के गोगरा-हाट स्थिंग्स क्षेत्र में युद्ध की मुद्रा में डटी दोनों देशों की सेनाओं को वहां से हटा लिया जाए। ऐसा कर भी लिया गया। लद्धाख के इस क्षेत्र को पेट्रोल वाइंट-15 यानी 'पीपी-15' के नाम से जाना जाता है, जिस पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन की सेनाएं मई 2020 से एक-दूसरे के सामने खड़ी थीं। इस सहमति का लक्ष्य दोनों ओर के सैनिकों को अपने-अपने नियंत्रण वाले इलाकों में पीछे भेजना और तनाव के दौरान खड़े किए गए सैन्य ढांचे को नष्ट करके दो से चार किमी चौड़ा ऐसा क्षेत्र बनाना है, जो बफर जॉन यानी असैन्य क्षेत्र का काम करे। इसका मतलब यह है कि भारत और चीन के बीच लद्धाख में चला आ रहा सैनिक तनाव अब खत्म हो गया है और अब हिंदू-चीनी भाई-भाई का प्रीत राग शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलाकों में चीन की आक्रामकता अभी बरकरार है। पीपी-15 को लेकर बनी सहमति से पहले भारत-चीन में गलवन घाटी, पेंगांग-त्सो और गोगरा के पीपी-17ए के तीन स्थानों पर पैदा हुए सैनिक विवादों में सहमति हो चुकी है, लेकिन इन चार स्थानों पर सहमति के बावजूद दौलत बेग ओल्डी के देपसांग और डेमचोक सेक्टर के चार्डिंग नाला जंक्शन में चीन की आक्रामक कार्रवाई से पैदा हुए विवाद को अभी हल किया जाना बाकी है। यह सगाल उठना स्वभाविक है कि आखिर वह चीनी सेना, जो दशकों से लद्धाख के भारतीय इलाकों पर गुपचुप कब्जा कर वहां जमे रहने को आदत बना चुकी थी, इस बार मई 2020 के बाद कब्जाए गए इलाकों को एक के बाद एक क्यों खाली कर रही है।

है? इसका जवाब उन तीन बिंदुओं में है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला बिंदु तो यह है कि चीनी

को पूरी उम्मीद थी कि भारतीय सेना चीनी सेना के सामने टिक नहीं पाएगी और गलवन पर नियंत्रण पाने के

बाद आजीवन राष्ट्रपति बनने और सर्वीच्च नेता हो जाने का उनका सपना पुरा हो जाएगा, लेकिन चीनी

सैनिक टकराव के कारण शाहीर्ड सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में कोई बड़ी अझरन आती है तो उनकी भद्र पिटेगी। साफ है कि भारत के साथ तनाव कम करना बहुत जरूरी हो चुका था। शी इसे लेकर पहले ही सदमें मैं थे कि चीन की गीदड़ भभकियों के आगे हर बार डर जाने वाली भारतीय सरकारों की परंपरा को मोदी ने पलट डाला। भारत की सेना ने न केवल चीनी सेना को लद्दाख के मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर मंच पर यह कहकर चीन की फजीहत की कि जब तक वह अपनी सेनाएं पहले की स्थिति में नहीं ले जाता, तब तक भारत उसके साथ दूसरे किसी विषय पर बात नहीं करगा। इसके चलते चीनी राष्ट्रपृष्ठ को यह चिंता भी सताने लगी थी कि उसके नेतृत्व वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में यदि प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लेने से मना कर दिया तो उनकी बहुत किरकिरी होगी। शायद इसीलए 17 जुलाई की 16वीं कोर कमांडर बैठक के दो महीने बाद चीन को अचानक पीपी-15 पर सहमति बनाने की याद आई। चीन को रास्ते पर लाने वाला तीसरा बिंदु यह है कि गलवन कांड के बाद भारत ने जिस पर्ती के साथ विश्व स्तर पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक और सैनिक किलेबंदी शुरू की, उसने उसके लिए नई परशानी पैदा कर दी थी। अमेरिका की पहल पर क्वाड को फिर से सक्रिय करने के अभियान में भागीदारी के साथ भारत ने जापान, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और फिलिपीन्स समेत ऐसे कई देशों से अपने आर्थिक और सैनिक संबंध सुधारने का जो अभियान शुरू किया, उसने भी चीन की परेशानी बढ़ाई। भारत की इन देशों को नेतृत्व दें पाने की क्षमता को देखते हुए भी शी चिनफिंग को भारत का महत्व समझ आने लगा था। पीपी-15 पर समझौता यकीन चीन के साथ सैनिक तनाव कम करने में उपयोगी है, क्योंकि आने वाले 5-10 साल भारत के लिए आर्थिक और सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ताजा सहमति का स्वागत करते हुए चीन की पुरानी करतूतों को भूलना महंगा पड़ सकता है। हमारे नीति निर्माताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के सभी फैसले तत्कालीन कठिनाई से निकलने और दीर्घकालीन फायदे पर केंद्रित रहते हैं और उनमें समझौतों के प्रति ईमानदारी या नैतिक जिम्मेदारी का लेशमात्र भी स्थान नहीं होता। मौके के मुताबिक पुरानी संधियों को कड़ेदान में डालना चीन की आदत है। यह एक तथ्य है कि अकेले लद्दाख मोर्चे पर आज भी चीन के 60 हजार सैनिक तनाव हैं, जो कभी भी उसकी मंशा को बदल सकते हैं।



राष्ट्रपति जैसे घरेलू राजनीतिक संकट में घिरे हुए हैं, उसमें भारत से हेकड़ी दिखाना उनके लिए बहुत महंगा सिद्ध हो सकता है। गलवन कांड और लद्धाख के दूसरे इलाकों में सैनिक कार्रवाई करते हुए शी

वह दौलत बेग ओल्डी के साथ  
गारिचन पर भी कब्जा जमा लेंगे।  
तरह कराकोरम हाइरे को  
तीय सेना के खतरे से स्थाई  
सात दिलाकर वह चीन में हीरों  
कर उभरेंगे। इस हीरोगीरी के

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन को करीब आते देख, उन्हें इसी में गणीमत लिये कि लद्दाख के तनाव को ठंडा करके भारत से टकराव को मुद्दा न बनने दिया जाए। शी की दूसरी चिंता यह थी कि अगर



